विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2025 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियां, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 300 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्त्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (ग्ँइ) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक ट्वीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियां, जैसे चंबल और बनास, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। खतरनाक कचरा अधिकांशत: नदियों और जलाशयों में बहा दिया जाता है जो राजस्थान के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यहां जल संसाधनों की कमी के कारण लोग पहले से ही सीमित जल स्त्रोतों पर निर्भर हैं।

> **आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।**

भूजल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। कई क्षेत्रों में भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड और भारी धातुओं की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सीवेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगसागर झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्राामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मलबे का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकराना और राजसमंद जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मलबा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। जोधपुर में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अनुचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे हवा में जहरीले धुएं का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रीसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

"वोकल फॉर लोकल" के आव्हान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.......

हेमेन्द्र सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसी ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस 'वोकल फॉर लोकल' के आव्हान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बुनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अज़रक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025' लागू की है।

■ 'स्वदेशी' से 'आत्मनिर्भरता' तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में 'वोकल फॉर लोकल' की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से पनपती स्थानीय पहचान :- देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान के सभी अंचलों में अलग-अलग पारिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। राज्य सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में विशिष्ट एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर की खूबसूरत पीलू जाल (वानस्पतिक प्रजाति), प्रतापगढ़ के थेवा आभूषण (उत्पाद) की बेजोड़ कलाकृति, अनोखी महक से सराबोर बीकानेर की मेथी (उपज), सदियों पुरानी धरोहर की छवि को उकेरता नागौर का मीरा स्मारक (पर्यटन स्थल), सिरोही की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सामर्थ्य को दर्शाती तीरंदाज़ी (खेल) इसके उदाहरण है। स्थानीयता एवं विशिष्टता के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान एवं विकास की पंचधारा से प्रदेश के सभी अंचलों के स्थानीय तत्व अब देश-विदेश में 'ब्रांड राजस्थान' बन रहे है।

आज 7 अगस्त का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। वैश्विक परिदृश्य में जब आज अन्य देश टैरिफ नीतियों की ओर बढ़ रहे है, तब हमारी कालजयी विरासत को संजोते हुए स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को विकल्प की बजाए आवश्यक रूप में अपनाने का मंत्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियाँ इसी दिशा में विकास और विरासत को संतुलित करते हुए एक नए एवं समृद्ध राजस्थान की बुनियाद रख रही है।

–हेमेन्द्र सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब भारत तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमें अपने संसाधनों, व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में वह क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जो आने वाले दशकों में देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाए। पेट्रोलियम सेक्टर इसकी सबसे अहम कड़ी है-और यह वही क्षेत्र है जहाँ बिखराव, विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता की खाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में उलझन और बार-बार सामने आती घपलों-चोरियों की खबरें आम हो चुकी हैं।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कितनी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ देश में तेल की आपूर्ति का जिम्मा उठाती हैं। लेकिन क्या ये बिखराव और प्रतिस्पर्धा जनता को वाकई बेहतर सेवा दे पा रही है? हर कंपनी का अपनी कंपाउंडिंग, अलग-अलग बफर स्टॉक्स, अलग स्टोरेज-ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अपनी अपनी लॉबी, नेताओं-अफसरों की हिस्सेदारी, पुराना नियम-कायदा, और अंत में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में अंतर। क्या कभी आपने सोचा-एक शहर में दो ब्रांड के पंप पर, एक ही दिन एक ही पेट्रोल के दाम-गुणवत्ता अलग कैसे हो सकते हैं?

अब समस्या सिर्फ कीमत या उपभोक्ता के भ्रम की नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लागत व पारदर्शिता की कमी की भी है। रोज़मर्रा के अख़बारों की हेडलाइन बनती "पेट्रोल डीजल चोरी", काला बाजारी, ट्रक-टैंकर घोटाले.. अभी ताजातरीन मामला एक अखबार की फ्रंट पेज पर, पाइप लाइन से क्रूड आयल चोरी जो कई दशकों से चल रही है और एक बड़े माफिया का रूप ले चुकी है जो अपने आप में सिस्टम की खामियों का आईना है। मर्जर से क्या-क्या बदल सकता है?

कल्पना कीजिए-यदि तीनो पेट्रोलियम कंपनियाँ मर्ज हो जाएं, उनके सभी संसाधन, पूंजी, पाइपलाइन, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, विपणन नेटवर्क एक जगह, एक छत्र-छाया के नीचे आ जाएं, तो कैसे खुलेगा तरक्की का नया रास्ता! कोई 'प्रीमियम' और कोई 'सामान्य' पेट्रोल की उलझन रहेगी ही नहीं। देश-भर में एक ही क्वालिटी, सबसे बेहतरीन ग्रेड का पेट्रोल-डीजल मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की लागत आधी से भी कम, व्यवस्था खातों किताबों के हिसाब से एकदम पारदर्शी।

बफर स्टॉक्स और इमरजेंसी स्टोरेज-जो आज हर कंपनी अलग बनाती-रखती है, वह एक सिस्टम में आ जाएगा।

जब डीलरशिप खुलेगी, तो न पारिवारिक/राजनीतिक सिफ़ारिश चलेगी, न अफसरशाही की पकड़ बचेगी-पारदर्शी नीलामी और ऑक्शन से आम आदमी को भी अवसर।

बाजार में एक ही ब्रांड, एक ही पेट्रोल-तो उपभोक्ता के मन का भ्रम भी दूर और भ्रष्टाचार को भी सीधी चोट।

जब वाहनों के लिए एक ही ग्रेड भारत का पेट्रोल-डीजल सरकार उपलब्ध कराएगी, तो प्रदूषण कम करने का लक्ष्य भी यही से साधा जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस पर नियंत्रण होगा।

वर्टिकल मैनेजमेंट: हर डिवीजन की सीधी जवाबदेही

मेगा पेट्रोलियम कंपनी में हर उत्पाद-चाहे वह क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो या की-लुब्रिकेंट, डीजल हो या एयर टरबाइन फ्यूल- प्रॉपेन सीएनजी या पेट्रोकैमिकल्स-उसके लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे। हर वर्टिकल के महानिदेशक की स्पष्ट जिम्मेदारी होगी कि इंपोर्ट/खरीद, रिफाइनिंग -प्रोसेसिंग से लेकर ग्राहक को डिलीवरी तक के हर खर्च-लाभ की सटीक बहीखाते तैयार हो जायेंगे। इस तरह सालाना जब एक विशाल जम्बो बैलेंसशीट बनेगी, तो सरकार और समाज जान पाएगा कि भारत का उत्पादन, उपभोग, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और भविष्य की ज़रूरतें एवं वर्तमान के हालातों से रूबरू होंगे।

अतीत से सबक, भविष्य का रास्ता

बहुत लोग कहते हैं-मर्जर में जोखिम है। मैं कहता हूं, यही वह वक्त है जब सरकार को साहसी निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी को ही ले लीजिए, जब इसके लिए 25 से भी ज्यादा विभागों का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां-भारत को सीखना होगा

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियां (590 अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक-चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आगे बढ़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:–

सऊदी अरामको (Saudi Aramco)

वार्षिक राजस्व: लगभग 590 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैपिटलाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical)

वार्षिक राजस्व: लगभग 487 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina)

वार्षिक राजस्व: लगभग 486 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 79 अरब अमेरिकी डॉलर

एक्सॉन मोबिल (ExxonMobil)

वार्षिक राजस्व: लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 445 अरब अमेरिकी डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC)

वार्षिक राजस्व: लगभग 365 अरब अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 202 अरब अमेरिकी डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 2,09,065 करोड़ रुपये है और इसके पास कुल रिज़र्व्स 1,72,716 करोड़ रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री 7,58,106 करोड़ रुपये तक पहुँचती है और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और रिज़र्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएल ने 4,40,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और 13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी, 90,475 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण और 49,016 करोड़ के रिज़र्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका शेयर 425 है। बिक्री 4,34,106 करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ 6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल इक्विटी पूंजी 20,173 करोड़ रुपये, कुल मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और कुल रिज़र्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484 करोड़ रुपये है और मिलाजुला शुद्ध लाभ 33,862 करोड़ रुपये तक पहुँचता है।

यदि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां मर्ज होकर एक "मेगा इंडिया पेट्रोलियम" कंपनी का रूप लेती हैं, तो उसके संभावित फ़ायदे और वैश्विक प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:–

भारत की 'मेगा कंपनी' का संयुक्त वार्षिक राजस्व लगभग 200-250 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे वह दुनिया की टॉप-5 तेल कंपनियों की कतार में आ सकती है।

बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी बढ़कर लगभग 200-300 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुँच सकती है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनता को पूरे देश में एक ही दर और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल-डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता भ्रांतियां और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग-अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महँगा है तो उसकी बिक्री नगण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान - हरियाणा के बॉर्डर पर देखा जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानत: 15-20 तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। सभी का इन्वेंटरी प्रबंधन खर्च मर्जर के बाद आधा हो जाएगा।

एकीकृत कंपनी देश के लिए निवेश, रोजगार, टेक्नोलॉजी और पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी ला सकती है।

ग्लोबल स्टेज पर भारत की ब्रांडिंग मज़बूत होगी और "वन ब्रांड, वन कंपनी, वन नेशन" का सपना साकार होगा।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भविष्य की जनेरशन को एक अनुकूल पर्यावरण।

नई कंपनी के बनने से सैकड़ों नई नौकरियाँ, टेक्निकल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार मौके।

इस तरह, भारत की एक विशाल पेट्रोलियम कंपनी विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने और उपभोक्ता जीवन आसान बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

देश के लिए, आम जनता के लिए

अब यह सिर्फ सरकार के सपने की बात नहीं-यह आम आदमी, टैक्सपेयर, व्यवसायी, किसान, व्यापारी, हर नागरिक के विकास का सपना है। भारत के हर कोने में एक ही दर, एक गुणवत्ता का पेट्रोल-डीजल, पारदर्शी सौदे, स्मार्ट व तेज वितरण। पाइपलाइन से गांव हो या मेट्रो सिटी, गैस-पेट्रोल के बेहतर इस्तेमाल की क्रांति।

अब बदलाव की ज़रूरत

क्या नई चुनौतियाँ नहीं होंगी? जरूर होंगी। बड़े बदलाव कभी भी बिना विरोध या टकराव के नहीं आते, लेकिन अगर लक्ष्य पारदर्शिता, दक्षता, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी और उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा देना है, तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा।

"एक कंपनी, एक ब्रांड, एक क्वालिटी, एक राष्ट्र"-अब समय है भारत को एशिया ही नहीं दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों के साथ बराबरी पर खड़ा देखें। सरकार, विशेषज्ञ, और समाज-सबको आगे आकर इस परिवर्तन की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाना होगा।

यदि आपको उसका कोई हिस्सा और विस्तार से चाहिए, या और भी संचारी, भावनात्मक या तथ्यपरक भाषा में चाहिए-तो आप निर्देश दें।

धन्यवाद,

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

राशिफल गुरूवार 7 अगस्त, 2025

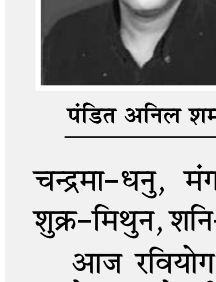

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन 2:01 तक, विष्कुम्भ योग प्रात: 6:42 तक, तैतिल करण दिन 2:28 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:11 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 2:01 से आरम्भ होगा। आज आखेटक त्रयोदशी और शिव पवित्रारोपण है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 10:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:50 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:07

मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
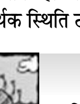
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेंगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कन्या

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे।

तुला
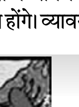
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मकर

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

मीन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।